https://farid.ps/articles/gaza_unga_resolution/hi.html

संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव

शांति के लिए एकजुट: गाजा में नागरिकों और मानवीय कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना

महासभा,

स्मरण करते हुए अपनी 3 नवंबर 1950 की प्रस्ताव संख्या 377 (V), जिसे "शांति के लिए एकजुट" के रूप में जाना जाता है, जो यह पुष्टि करता है कि जब सुरक्षा परिषद अपने स्थायी सदस्यों के बीच एकमत न होने के कारण अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी को निभाने में विफल रहती है, तो महासभा को तत्काल इस मामले पर विचार करना चाहिए और उपयुक्त सिफारिशें जारी करनी चाहिए, जिसमें आवश्यक होने पर सशस्त्र बलों का उपयोग भी शामिल है, ताकि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बहाल की जा सके,

पुनः पुष्टि करते हुए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांतों और उद्देश्यों, विशेष रूप से मानवाधिकारों को बनाए रखने, न्याय को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्रतिबद्धता,

स्मरण करते हुए मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR), जो 10 दिसंबर 1948 को अपनाई गई थी, जो सभी मनुष्यों के जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा के अविच्छेद्य अधिकारों को स्थापित करती है और यह जोर देती है कि "फिर कभी नहीं" का अर्थ सभी के लिए, बिना किसी भेदभाव के, फिर कभी नहीं होना चाहिए,

पुनः पुष्टि करते हुए 1949 की जेनेवा संधियों और उनके अतिरिक्त प्रोटोकॉल, जो सशस्त्र संघर्षों के दौरान नागरिकों और मानवीय कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करते हैं, और यह याद दिलाते हुए कि संघर्ष के सभी पक्ष इन दायित्वों से बंधे हैं,

स्मरण करते हुए 1948 की नरसंहार की रोकथाम और दंड संधि, जो राज्यों को नरसंहार के कृत्यों को रोकने और दंडित करने के लिए बाध्य करती है, और गहरी चिंता के साथ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के 26 जनवरी 2024 के अस्थायी उपायों के निष्कर्षों पर ध्यान देते हुए, जिसमें इजरायल को गाजा में फिलिस्तीनियों को नरसंहार के जोखिम से बचाने के लिए तत्काल और प्रभावी उपाय करने का आदेश दिया गया, जिसमें पर्याप्त मानवीय सहायता सुनिश्चित करना और बुनियादी सेवाओं को सक्षम करना शामिल है,

पुनः पुष्टि करते हुए संरक्षण की जिम्मेदारी (R2P) के सिद्धांत को, जिसे 2005 में महासभा ने समर्थन दिया था, जो यह मानता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है कि वह आबादी को नरसंहार, युद्ध अपराधों, नस्लीय सफाई और मानवता के खिलाफ अपराधों से बचाए जब कोई राज्य स्पष्ट रूप से ऐसा करने में विफल रहता है, और यह जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से सामूहिक कार्रवाई लेने को शामिल करती है,

गहरी चिंता के साथ नोट करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बार-बार की विफलता गाजा में मानवीय संकट को संबोधित करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने में, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वीटो के उपयोग के कारण, हाल ही में 20 फरवरी 2024 को, एक तत्काल युद्धविराम की मांग करने वाले प्रस्ताव को अवरुद्ध करने के लिए, जिससे परिषद की अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी में बाधा उत्पन्न हुई,

चिंता व्यक्त करते हुए इजरायल द्वारा सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का पालन न करने पर, जिसमें प्रस्ताव 2728 (2024) शामिल है, जो तत्काल युद्धविराम की मांग करता है, साथ ही ICJ के कानूनी रूप से बाध्यकारी अस्थायी उपायों का पालन न करना, जैसा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 28 फरवरी 2024 को दस्तावेज किया, जिसमें बताया गया कि इजरायल पर्याप्त मानवीय सहायता सुनिश्चित करने में विफल रहा और उसने अपनी सैन्य कार्रवाइयों को जारी रखा, जिसमें रफाह में वृद्धि की योजनाएं शामिल हैं, जो नागरिकों के लिए और अधिक विनाशकारी परिणामों का जोखिम उठाती हैं,

गंभीर रूप से चिंतित गाजा में चल रहे मानवीय संकट से, जो व्यापक विस्थापन, खाद्य असुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच और नागरिकों और मानवीय कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने की विशेषता रखता है, जैसा कि रियल इंस्टीट्यूटो एल्कानो ने 1 मार्च 2024 को रिपोर्ट किया, जो इस संदर्भ में R2P को प्रभावी ढंग से लागू करने में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की विफलता को उजागर करता है,

स्वीकार करते हुए कि गाजा में मानव पीड़ा का पैमाना, जिसमें बड़े पैमाने पर नागरिक हताहत, अवरोधों और सैन्य कार्रवाइयों के कारण भयावह जीवन स्थितियां शामिल हैं, संरक्षण की जिम्मेदारी के लागू करने के लिए एक स्पष्ट और तत्काल मामला प्रस्तुत करता है, और यह कि कार्रवाई न करने से अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता कमजोर होती है,

निर्धारित करते हुए कि गाजा की स्थिति अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है, जिसके लिए महासभा द्वारा अपने "शांति के लिए एकजुट" जनादेश के तहत तत्काल और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि नागरिकों और मानवीय कार्यकर्ताओं की रक्षा की जा सके और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को बनाए रखा जा सके,

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय IV के तहत और प्रस्ताव 377 (V) के अनुसार कार्य करते हुए,

---

मुख्य परिचालन खंड

1. **मांग करता है** गाजा में तत्काल और निरंतर युद्धविराम ताकि सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोका जा सके, नागरिकों की रक्षा की जा सके और मानवीय सहायता की सुरक्षित और अबाधित डिलीवरी संभव हो सके, जो ICJ के अस्थायी उपायों और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुरूप हो;

2. **आह्वान करता है** संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में गाजा में एक अंतरराष्ट्रीय संरक्षण बल की तत्काल तैनाती के लिए ताकि नागरिकों और मानवीय कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, उन्हें और हिंसा से बचाया जा सके और भोजन, चिकित्सा आपूर्ति और आश्रय सहित जीवन रक्षक सहायता की डिलीवरी को सुगम बनाया जा सके;

3. **सभी सदस्य राज्यों से आग्रह करता है** कि वे अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें, जिसमें ICJ के निर्णय और नरसंहार संधि शामिल हैं, इजरायल को किसी भी प्रकार की सैन्य, वित्तीय या कूटनीतिक सहायता को रोककर जो गाजा में अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन में योगदान दे सकती है;

4. **अनुरोध करता है** उन सदस्य राज्यों से जो सैन्य सहायता प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, कि वे अंतरराष्ट्रीय संरक्षण बल不思議なことに、インターナショナル・クリミナル・コート（ICC）の調査を迅速化し、戦争犯罪や人道に対する罪の疑いのある行為について、ICCと完全 सहयोग करने के लिए सदस्य国हरूको आग्रह गर्दछ;

5. **उल्लेख गर्दछ** इजरायल वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको यस प्रस्तावको कार्यान्वयनमा कुनै पनि आपत्तिलाई हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) मा निर्णयको लागि पठाउँछ, र पुनः पुष्टि गर्दछ कि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघनलाई सम्बोधन गर्न न्यायका ढोकाहरू खुला रहन्छन्;

6. **महासचिवलाई अनुरोध गर्दछ** कि यो प्रस्तावको कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण बलको स्थापना, मानवीय सहायताको वितरण र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघनको लागि जिम्मेदारीको प्रगतिबारे ३० दिनभित्र महासभालाई प्रतिवेदन गर्न;

7. **निर्णय गर्दछ** कि यो विषयमा संलग्न रहनेछ र यदि गाजाको स्थिति थप बिग्रन्छ वा यो प्रस्तावमा उल्लिखित उपायहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गरिएन भने, एक आपतकालीन विशेष सत्र आयोजित गर्नेछ।